जेएनयू नक्सली और आतंकवादी मुझे मार देंगे: पीएम मोदी

मैंने नक्सली और आतंकवादी को समाप्त करने का संकल्प लिया : सीएम मोदी

ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष रिपोर्ट

फ़रीदाबाद, दिल्ली सीमा पर, सूरजकुंड के करीब लेक व्यू पार्क की दूरी सुधा भारद्वाज के निवास स्थल चार्म्सवुड सोसाइटी से करीब 1 किलोमीटर है। वहां गार्ड ने सुधा भारद्वाज का नाम सुनने भर से बताया हम गलत पते पर हैं और उनके घर का सही रास्ता दिखाया। 'रोज का मिलना जुलना होता था भाई साहब हमारा सुधा जी से, इतनी शालीन और मददगार महिला को फंसाया गया है क्योंकि सरकार को दिक्कत है ऐसे लोगों से,' ये कहना था अगले सिक्यूरिटी गार्ड का जो चार्म्सवुड विलेज के एफ ब्लॉक में आने जाने वाले लोगों की एंट्री अपने रजिस्टर में दर्ज करने के साथ ही उनपर नजर भी रखता है।

छत्तीसगढ़, रायगढ़ के रहने वाले लाकड़ा को फ़रीदाबाद आये एक माह ही हुआ है। लाकड़ा इस सोसाइटी में सफाई का काम करते हैं और सिर्फ एक महीने में सुधा भारद्वाज के नाम से बेतरह वाकिफ हो गए हैं। सुधा जी के रहते हम जैसे छोटे कामगारों को कोई परेशान नहीं कर पाता है। इतने पर ही अपनी बात खत्म कर वे फिर सड़क की सफाई में लीन हो गए।

थोड़ा आगे चलने पर 50 वर्षीय कृपाधन ठेले पर अपने 15 वर्षीय बेटे के साथ सब्जियां सजा रहे थे। सुधा एक नक्सली है, सुनते ही उनका चेहरा तमतमा गया पर किसी डर ने जैसे कंठ को दबाये रखा। दबी जबान में सही, पर सुर्ख चेहरे से बोले आप पत्रकार लोग किसी को जो चाहो बोल लो, पर सुधा जी को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कृपाधन का बेटा विजय बोला कि दीदी हमें पढ़ाती भी थी, आगे से उल्टे हाथ मुड़ना और आखिरी वाली बिल्डिंग उन्ही की है जहाँ पुलिस वाले भी बैठे होंगे।

ऐसे शहरों में जहाँ एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का नाम तक न जानते हों वहाँ सुधा को दो दो किलोमीटर दूर सड़कों पर खड़े रेहड़ी पटरी वाले और सभी गार्ड तक जानते हैं। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि प्रधानमंत्री की हत्या साजिश करने वाले को तो सब जान ही जाते हैं बल्कि सुधा का ऐसे हाशिये पर पहुँचे कमजोरों के लिए मददगार स्वभाव होना है। ये कहना था इसी सोसाइटी में रहने वाली एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का जो आज के माहौल में अपना नाम नहीं बताना चाहती थीं।

62 वर्षीय किरन शाहीन, सुधा की परम मित्रों में एक हैं। वे दिल्ली नोएडा से सुधा से मिलने आयी थीं। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्री रंगनाथ भारद्वाज और कृष्णा भारद्वाज की बेटी सुधा का जन्म 1961 में अमेरिका में हुआ। 10 वर्ष की उम्र में सुधा अपनी माँ के साथ भारत आई। जेएनयू में अर्थशास्त्र विभाग की संस्थापक कृष्णा भारद्वाज चाहती थीं कि उनकी बेटी वो सब करे जो वो करना चाहती है। इसी प्रेरणा से वयस्क होते ही सुधा अमेरिका का ख्याल छोड़ आइआइटी कानपुर से पढ़ने लगी। इस दौरान दिल्ली के साथियों के साथ ही झुग्गी बस्ती में मजदूरों के बच्चों को पढ़ना और उनके राजनैतिक हक की लड़ाई शुरू की। छत्तीसगढ़ जा कर बस जाना और वहाँ के सीमेंट मजदूरों और दूसरे लाखों मजदूरों और आदिवासियों के हक की आवाज बन सुधा अब कॉर्पोरेट की दलाल बन चुकी मोदी की भाजपा के आँखों की

'आंतकी' सुधा का 'नक्सली' ठिकाना!

किरकिरी बन गई है शायद।

हरियाणा पुलिस की जिप्सी समेत तीन पुलिस वाले सुधा के घर के नीचे पहरा दे रहे हैं कि कहीं कोई चिड़िया न पर मार दे। इतनी बड़ी साजिशकर्ता, जिसका मामला स्वयं सुप्रीम कोर्ट देख रहा हो, की इतनी हल्की ! सूरजकुंड थाने के बेहद नजदीक वर्षों से इतनी खूंखार नक्सल डेरा जमाये बैठी है और प्रधानमंत्री मोदी जिसे फासिस्ट तक कहने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं को मारने की साजिश भी रच गई।

पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग सकी आज तक? इस बात पर पुलिस पार्टी के इंचार्ज एएसआई साहब की दलील काबिलेगौर है। उनके अनुसार पुलिस किसी को देख कर कैसे पता लगा लेगी की वो आतंकवादी है या नहीं, वो भी तब जब उसका आधारकार्ड भी बना हो। साथ बैठे सिपाही ने चार कदम आगे बढ़ कर जोड़ा कि भई यो महिला घनी ही पढी लिखी है, अम्रीका ताई ना जाने के पढ के आई है।

हमने सवाल किया कि क्या आतंकवादी को जानने के लिए शक्ल देखी जाती है? सीआइडी, आइबी, एनआइए सरीखी एजेंसियों को कोई खबर ही नहीं। और जो सुधा कानून की इतनी ज्ञाता है ही तो क्या वो ये नहीं जानती होगी कि ईमेल से ऐसी बातें उसके लिए संकट पैदा करेंगी। ऐसी बेवकूफी तो सड़क छाप चोर भी न करे?

अपने एक सितारे रैंक में चार और सितारे जोड़ते हुए एएसआई साहब ने अपनी पहली बात को काटते हुए कहा कि भाई साब ये जो घने पड़े लिखे होते ना कत्तई मूरख होया करैं, ओर फेर चोर गलती तो करै ही करै। इस सोच और ट्रेनिंग के साथ हमारी सुरक्षा में जुटी पुलिस से आम नागरिक क्या उम्मीद कर सकता है? जो ये मानता हो कि जो ज्यादा पढ़ा है वो शातिर है या जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो मूर्ख है। दोनों ही बातों में प्रधानमंत्री मोदी की एंटायर पोलिटिकल साइंस वाली डिग्री की ही विजय दिख रही है। मोदी जी को पहले पता होता ये तो उनकी डिग्री को लेकर शायद स्मृति ईरानीयों को इस कदर झूठ न बोलना पड़ा होता।

खैर पुलिस से संविधान की रक्षा की उम्मीद वैसी ही है जैसी मोदी जी से सच सुनने की उम्मीद करना। अब गेंद उच्चतम न्यायालय के पाले में है। देश के लोकतंत्र में जन का विश्वास बना रहे इसके लिए सुधा के साथ जल्द से जल्द न्याय होना जरूरी है।

सुधा की गिरफ्तारी को एसपीजी टेस्ट से गुजारना चाहिए !

(मजदूर मोर्चा विशेष)

मोदी पूरी तरह सुरक्षित हैं, एसपीजी में अपने बारह वर्षों के आधार पर यह कह सकता हूँ। प्रधानमन्त्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी से चौकस व्यवस्था हो ही नहीं सकती। लेकिन उनका झूठ सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सुधा और अन्य सक्रिय मानवाधिकार कर्मियों पर उनकी हत्या के षड्यंत्र के आरोप को एसपीजी सुरक्षा के ही टेस्ट से आँका जाना मुश्किल भी नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के सामने भी संविधान के शरीर की रक्षा का नहीं उसकी आत्मा को बचाने का सवाल होगा। कोर्ट के सामने हमेशा ही दो पक्ष होते हैं जिनमें एक सही साबित होता है। लेकिन इस बार जो दो पक्ष हैं उनमें एक संविधान की आत्मा का हनन करने वाला है। मुझे तनिक भी शक नहीं कि वह कौन सा पक्ष है!

एसपीजी के इतिहास में किसी प्रधानमन्त्री की हत्या की साजिश का पहला मामला दर्ज होने का सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर ही बंधना था। नरेंद्र मोदी के नाम तमाम तरह के रिकॉर्ड हैं, बतौर मुख्यमंत्री गुजरात भी उनकी हत्या की साजिश के मुक़दमे बनाये गये। अब बतौर प्रधानमन्त्री उनकी हत्या की साजिश का मुक़दमा दर्ज हो गया।

श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रधानमन्त्री रहते हत्या हुयी थी लेकिन तब एसपीजी अस्तित्व में नहीं होती थी। राजीव गाँधी की जब साजिशन हत्या हुयी, वे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हो चुके थे और तत्कालीन नियमों के अनुसार उनकी सुरक्षा में एसपीजी नहीं थी। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के रूप में चंद्रशेखर के समय में एसपीजी पर सुरक्षा का दायित्व आ चुका था। एक बार उन पर ट्रेन यात्रा के दौरान हमले की गंभीर स्थिति पैदा हो गयी थी पर वह आकस्मिक विवाद से बनी न कि किसी साजिश के तहत।

मोदी की हत्या के षड्यंत्र में आरोपित साजिशकर्ताओं की उम्र साठ से अस्सी के

दशक में चल रही है। उनकी गिरफ्तारियां किस सुविधा से संपन्न हुयी हैं; सभी अपने-अपने घर में बैठे हुए थे कि महाराष्ट्र पुलिस आये और उन्हें पकड़ ले। दरअसल, कहना पड़ेगा कि गत जून से ही महाराष्ट्र पुलिस उनसे यह इन्तजार करवा रही होगी। पुलिस के अपने दावों के अनुसार, तब से उनका नाम पुलिस के पास आ चुका था।

सोचिये, दुनिया में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमन्त्री की हत्या की साजिश का मुक़दमा दर्ज हुआ हो और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा ले जाने पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी हो।

आपको हंसी तो नहीं आ रही? क्या महाराष्ट्र पुलिस ऐसे ही स्वयंसिद्ध फर्जी मामले बनाती है और वह भी प्रधानमन्त्री का नाम लेकर। नहीं, पुलिस कैसी भी गयी गुजरी हो ऐसी हास्यास्पद कहानी नहीं बनायेगी।

कहीं यह आईबी की स्क्रिप्ट तो नहीं जो रिपोर्ट गढ़ने में तो मास्टर है पर केस बांधने में फिसड्डी।

कुछ बातें बिलकुल भी मेल नहीं खातीं। चलन को देखें तो माओवादी अपनी मांद से बाहर आकर राजनीतिक शिकार नहीं करते। और मोदी का किसी माओवादी मांद में जाने का कार्यक्रम कभी बना नहीं। यदि जून के महीने से ही मोदी की हत्या के आतंकी षड्यंत्र का आभास महाराष्ट्र पुलिस को लग गया था तो इस बेहद गंभीर मामले की आगे की छान-बीन नियमानुसार एनआईए को क्यों नहीं सौंपी गयी ?

हुआ यह भी कि कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या की कोर्ट निर्देशित सीबीआई जांच में हिन्दू संगठन के भावी हत्याओं की योजना के राज खुल गये और महाराष्ट्र पुलिस को उनके लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ी। हिंदुत्व की राजनीति पर यह चोट और वह भी अपनी ही पुलिस की मार्फत कहाँ बर्दाश्त होनी थी। तो उसी पुलिस से अब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लपेटे में लेने को कहा गया। यानी संतुलन बैठाने में बुरी तरह असंतुलित हो गयी पुलिस की कार्यवाही।

जाहिर है, महाराष्ट्र पुलिस अपनी कहानी के समर्थन में तरह-तरह के बयान और दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। प्रेस कांफ्रेंस में उसने अपने तरकश के कुछ तीर दिखाये भी हैं। बयान, पुलिस को लिखने होते हैं, वह जो चाहे लिख ले। साइबर युग में फर्जी मेल बनानी भी क्या मुश्किल हैं। तब भी कोई अदालत इन साक्ष्यों को प्रथम दृष्टा अस्वीकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट भी हद से हद आगे और जांच का आदेश दे सकती है।

तो क्या सप्रीम कोर्ट में संविधान की आत्मा की हत्या होने दी जायेगी? अब मैं उस एसपीजी टेस्ट पर आता हूँ जिसका जिक्र इस आलेख के शुरू में किया गया। एसपीजी की कार्य संस्कृति के आयाम रहे हैं- फूल प्रूफ और फेल प्रूफ सिक्यूरिटी। इसे हासिल करने में इंटेलिजेंस इनपुट की अहम भूमिका रहती है। यह इनपुट सभी सम्बंधित सुरक्षा और पुलिस एजेंसीज से वांछित कार्यवाही के लिए साझा किया जाता है।

सत्रह अगस्त की अटल बिहारी वाजपेयी की शव यात्रा में मोदी का चार किलोमीटर पैदल चलना, मीडिया या आम जन को बेशक चौंका गया हो, एसपीजी और आईबी को निश्चित ही इसकी पूर्व जानकारी होगी। तदनुसार आईबी ने इंटेलिजेंस इनपुट भी एसपीजी समेत सभी सम्बंधित को भेजा होगा। जाहिर है, उसमें मौजूदा मामले में आरोपित षड्यंत्र कारियों का भी विशेष जिक्र रहा होगा।

आरोपियों में नवलखा और सुधा तो दिल्ली और पड़ोसी फरीदाबाद के ही निवासी हुये। दोनों पुलिस की ओर से उनकी निगरानी की विस्तृत व्यवस्था जरूर की गयी होगी। इसी तरह अन्य आरोपियों की समुचित निगरानी के बंदोबस्त सम्बंधित राज्य पुलिस ने किये होंगे। हालाँकि, उस दौरान इन आरोपियों में से किसी की भी गतिविधि पर रोक लगने के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। दिलचस्प होगा, यदि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी के लिए ये इंटेलिजेंस इनपुट और निगरानी कवायदें तलब हों।

क्या इन्हें नए सिरे से गढ़ा नहीं जा सकता? क्यों नहीं! लेकिन, पुलिस मित्रों, जितना गढ़ोगे उतना गिरोगे!

-विकास नारायण राय, पूर्व आईपीएस

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06